भारतीय कृषि के समग्र विकास की दिशा में सार्थक प्रयास

डॉ जगदीप सक्सेना
पूर्व मुख्य संपादक, आईसीएआर (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद), नई दिल्ली।
ईमेल: jagdeepsaxena@yahoo.com

यह वर्ष कृषि क्षेत्र के लिए उल्लेखनीय रहा है, जिसमें कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं, जैसे रिकॉर्ड खाद्य उत्पादन, फसलों का अब तक का सबसे अधिक एमएसपी, ऐतिहासिक बजट आवंटन और निश्चित रूप से अनुकूल मानसून। इस गति को आगे बढ़ाते हुए, भारत सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादकता, लाभप्रदता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं और पहल शुरू की हैं।

कृषि के समावेशी विकास और किसानों के कल्याण के लिए छह सूत्री कार्यनीति का भी अनावरण किया गया। भारतीय कृषि को भविष्य के लिए तैयार और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए चल रही योजनाओं को अत्याधुनिक तकनीकों के साथ और मजबूत किया गया। पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों का समाधान/शमन करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और उसके बाद इसका विस्तार, प्रमुख जोर वाले क्षेत्रों में से एक रहा है। छोटे और सीमांत किसान, महिलाएं और युवा अपने वित्तीय समावेशन और सशक्तीकरण के लिए कृषि के सभी क्षेत्रों में फोकस में रहे।

संसाधन और रिकॉर्ड

बजट आवंटन (2024-25) ने मौजूदा योजनाओं और बजट में प्रस्तावित भविष्य की पहलों का समर्थन करने के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक उच्च स्तर हासिल किया और इसने कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। कृषि अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और सक्षम मानव संसाधन विकसित करने के लिए आवंटन को बढ़ाकर 9,941.09 करोड़ रुपये कर दिया गया। कृषि के संबद्ध क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को 4,521 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जबकि मत्स्य-पालन क्षेत्र को 2,616 करोड़ रुपये का अनुदान मिला। अधिक आवंटन मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे के विकास को सुविधाजनक बनाकर डेयरी, पशुधन और मत्स्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए है। उत्पादन पक्ष की ओर नज़र डालें तो, इस वर्ष (2023-24) 3322.98 एलएमटी (लाख मीट्रिक

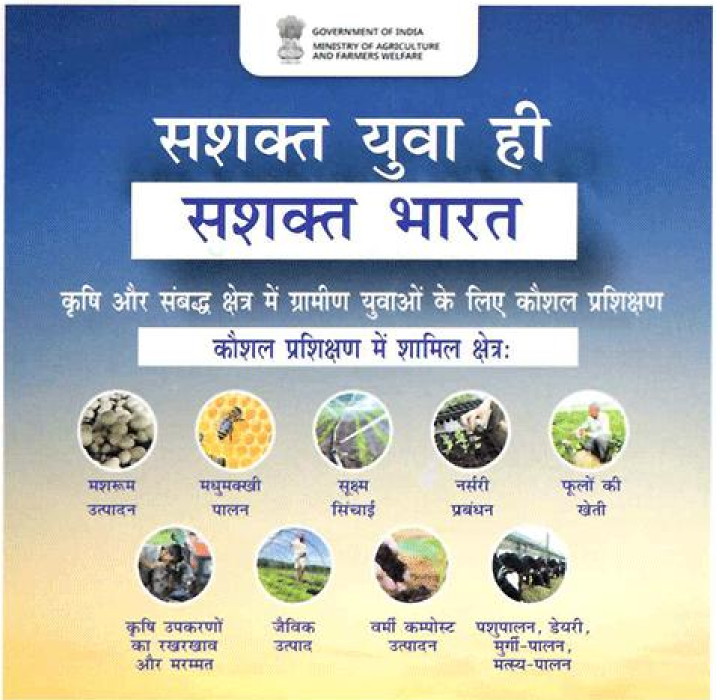

टन) का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हासिल किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 26.11 एलएमटी अधिक है। यह उल्लेखनीय वृद्धि मुख्य रूप से चावल (1378.25 एलएमटी), गेहूं (1132.92 एलएमटी) और श्री अन्न (175.72 एलएमटी) के अधिक उत्पादन के कारण हुई है। तिलहनों में, मिशन मोड में विशेष पहल के कारण सफेद सरसों और सरसों का रिकॉर्ड उत्पादन हासिल किया गया। तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2023-24 के दौरान दालों का राष्ट्रीय उत्पादन 163.23 लाख टन (2015-16) से बढ़कर 244.93 लाख टन हो गया है। वर्ष 2023-24 में फलों का उत्पादन 2022-23 की तुलना में 2.29 प्रतिशत बढ़कर 112.73 मिलियन टन होने की उम्मीद है। बागवानी क्षेत्र में, फलों के अलावा, शहद, फूल, बागान फसलों, मसालों और सुगंधित और औषधीय पौधों (अंतिम अनुमान) में भी अधिक उत्पादन दर्ज किया गया। कुल मिलाकर, सब्जियों का उत्पादन लगभग 205.80 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जिसका मुख्य कारण टमाटर, गोभी, फूलगोभी, गाजर, टैपिओका, भिंडी आदि के उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि है।

विपणन सीजन 2024-25 और 2025-26 के लिए क्रमशः सभी अनिवार्य खरीफ और रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि की गई। सभी फसलों में, यह वृद्धि अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना एमएसपी तय करने की सरकार की नीति के अनुरूप है। हालांकि, खरीफ फसलों के घोषित एमएसपी में उत्पादन की औसत लागत पर अपेक्षित मार्जिन सबसे अधिक बाजरा (77 प्रतिशत) के मामले में था, उसके बाद तुअर (59 प्रतिशत), मक्का (54 प्रतिशत) और उड़द (52 प्रतिशत) का स्थान रहा। रबी फसलों के घोषित एमएसपी के मामले में उत्पादन की औसत लागत पर अपेक्षित मार्जिन सबसे अधिक गेहूं (105 प्रतिशत) के लिए था, उसके बाद सफेद सरसों और सरसों (98 प्रतिशत), मसूर (89 प्रतिशत), चना (60 प्रतिशत) और जौ (60 प्रतिशत) का स्थान रहा। एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि सफेद सरसों और सरसों (300 रुपये प्रति क्विंटल) के लिए की गई है, इसके बाद मसूर की कीमत 275 रुपये प्रति क्विंटल है। बढ़ी हुई एमएसपी किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करती है और फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा देती है। हाल के वर्षों में, दालों, तिलहनों और पोषक अनाज (श्री अन्न) के लिए उच्च एमएसपी की पेशकश करके अनाज के अलावा अन्य फसलों की खेती को बढ़ावा दिया गया है।

सितंबर के आखिर में जब दक्षिण-पश्चिम मानसून ने वापसी शुरू की, तो पूरे भारत में 5 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई। हालांकि, इसकी शुरुआत धीमी रही, जिसने बाद के आधे हिस्से में गति पकड़ी, जिससे किसानों को बुवाई में मदद मिली। नतीजतन, धान, तिलहन और दलहन में पिछले साल (सितंबर 2024 तक) की तुलना में क्रमशः 2.2 प्रतिशत, 1.5 प्रतिशत और 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। देर से और अधिक बारिश के कारण, जलाशयों का वर्तमान भंडारण पिछले साल के लगभग 123 प्रतिशत और पिछले 10 वर्षों के सामान्य भंडारण का 118 प्रतिशत है। मिट्टी की नमी में भी सुधार हुआ है और यह दक्षिणी और उत्तरी राज्यों के अधिकांश हिस्सों में नौ साल के औसत से बेहतर या उसके बराबर है। इससे गेहूं और चना जैसी सर्दियों की फसलों को फायदा होगा। अच्छे मानसून ने बेहतर समग्र कृषि उत्पादकता की उम्मीदें जगाई हैं।

पहल और हस्तक्षेप

कृषि के समग्र विकास की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाते हुए, केंद्र सरकार ने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए सात प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी। योजनाओं का कुल परिव्यय 14,235.30 करोड़ रुपये है। 'डिजिटल कृषि मिशन' सबसे प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य किसान-केंद्रित डिजिटल समाधान प्रदान करके कृषि क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन करना है। शुरुआत में, मिशन के तहत तीन प्रकार के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) बनाए जाएंगे, जैसे कि एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (केडीएसएस) और मृदा प्रोफ़ाइल मैपिंग। एग्रीस्टैक किसानों को कुशल, आसान और तेज़ सेवाएं और योजनाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। 'आधार' की तरह ही, प्रत्येक किसान के लिए एक डिजिटल पहचान बनाई जाएगी, जिसे विभिन्न किसान-आधारित डेटाबेस, जैसे भूमि रिकॉर्ड, पशुधन स्वामित्व, बोई गई फसलें, पारिवारिक विवरण, योजनाएं और प्राप्त लाभ आदि से जोड़ा जाएगा। केडीएसएस को फसलों, मिट्टी, मौसम, जल संसाधनों आदि जैसे मापदंडों पर रिमोट सेंसिंग-आधारित

जानकारी को एकीकृत करने के लिए एक व्यापक भू-स्थानिक प्रणाली बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक अन्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म कृषि उत्पादन का सटीक अनुमान लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मिशन से लगभग 2.5 लाख प्रशिक्षित स्थानीय युवाओं और कृषि सखियों को रोज़गार के अवसर मिलने की उम्मीद है और यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे किसानों को विभिन्न कृषि पद्धतियों से संबंधित समय पर मार्गदर्शन और सेवाएं मिलें। मिशन का कुल परिव्यय 2,817 करोड़ रुपये है, जिसमें 1,940 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा शामिल है।

किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रति तैयार करने और सतत खाद्य एवं पोषण सुरक्षा बनाए रखने के लिए 3,979 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ एक विशेष पहल को मंजूरी दी गई। पौधों के आनुवंशिक संसाधनों का कुशल प्रबंधन और फसलों के आनुवंशिक सुधार लक्ष्य को प्राप्त करना आदि पहचान किए गए प्रमुख मार्ग हैं। विभिन्न उभरती चुनौतियों के बीच, अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके प्राकृतिक प्रतिकूलताओं पर काबू पाने के लिए कृषि छात्रों और शोधकर्ताओं को तैयार करने की योजना को मंजूरी दी गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसे संचालित करने के लिए नामित प्रमुख एजेंसी है, जिस पर कुल 2,291 करोड़ रुपये का परिव्यय है। अनुसंधान

के अलावा, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कृषि-शिक्षा का भी आधुनिकीकरण किया जाएगा। मुख्य कृषि के अलावा, पशुधन और डेयरी उद्यमों से किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक पहल की गई है। इसमें पशुधन और डेयरी प्रबंधन के विभिन्न घटक शामिल हैं, जिसमें पशु आनुवंशिक संसाधनों में

कृषि आयात और निर्यात-प्रमुख निर्णय

प्याज़: इससे पहले, 550 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य और 40 प्रतिशत का निर्यात शुल्क निर्यात को प्रतिबंधित कर रहा था। बहुत अधिक कीमतों के कारण विदेशी आयातक भारत से प्याज खरीदने से कतराते थे। सरकार ने न्यूनतम निर्यात मूल्य पर प्रतिबंध को पूरी तरह से हटाने और निर्यात शुल्क को 40 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इससे प्याज उत्पादकों को निश्चित रूप से व्यापक धन वृद्धि मिलेगी।

बासमती चावल: यह भारत के कृषि निर्यात की एक प्रमुख वस्तु है जिसका वैश्विक बाजार में महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन बासमती चावल की किस्मों पर निर्यात प्रतिबंध के कारण बासमती निर्यातकों को झटका लगा, जिनकी कीमत 800 से 950 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन है। इस प्रतिबंध के कारण हमारे उत्पादक वैश्विक बाजार में अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। बासमती चावल निर्यातकों के पक्ष में निर्णय लेते हुए अब इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। इस कदम से अब बासमती चावल किसानों को अपने प्रीमियम उत्पाद के लिए विदेशी बाजार में पुनः जगह बनाने में मदद मिलेगी।

खाद्य तेल: भारत घरेलू मांग को पूरा करने के लिए खाद्य तेलों के आयात पर बहुत अधिक निर्भर करता है। हालांकि, पाम और सोया तेल की कम अंतरराष्ट्रीय कीमतें और पाम, सोया और सूरजमुखी तेल के आयात पर शून्य बेसिक सीमा शुल्क उनके घरेलू मूल्यों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा था। सरकार ने कच्चे खाद्य तेल (जैसे पाम, सोया और सूरजमुखी) पर प्रभावी आयात शुल्क को 5.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 27.5 प्रतिशत और रिफाइंड तेल पर 13.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 35.75 प्रतिशत करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इससे तिलहन किसानों के पक्ष में घरेलू रूप से उत्पादित खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि होने की उम्मीद है।

एकीकृत कृषि-निर्यात सुविधा: सरकार ने जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई में भारत की पहली एकीकृत कृषि-निर्यात सुविधा के निर्माण को मंजूरी दी है। यह कृषि-लॉजिस्टिक्स में क्रांति लाने और अपव्यय को कम करने के लिए 284.19 करोड़ रुपये की पीपीपी परियोजना है। यह सुविधा लॉजिस्टिक्स में अक्षमताओं को दूर करेगी, कई प्रकार की हैंडलिंग को कम करेगी और कृषि उत्पादों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाएगी। इसके अलावा, इससे किसान सशक्त होंगे, रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और निर्यात क्षमता बढ़ेगी।

सुधार भी शामिल है। कुल 1,702 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ स्वीकृत इस योजना का उद्देश्य पशु चिकित्सा शिक्षा का आधुनिकीकरण करना भी है। टिकाऊ बागवानी पर एक नई योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में युवाओं को आकर्षित करने के लिए इसे और अधिक लाभदायक और आजीविका-उन्मुख बनाना है। इसके अलावा, पारंपरिक बागवानी फसलों के अलावा, इस पहल में बागान फसलों, मसालों और औषधीय और सुगंधित पौधों से किसानों की आय बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस योजना को कुल 1,129.30 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई थी। पानी, मिट्टी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के कुशल और टिकाऊ प्रबंधन के लिए 1,115 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर एक योजना को मंजूरी दी गई थी। 'कृषि विज्ञान केंद्रों' (केवीके) के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से एक योजना के माध्यम से 'लैब-टू-लैंड' के तहत गतिविधियों को और अधिक परिष्कृत और मजबूत किया जाएगा। ये जिला-स्तरीय ईकाइयां विभिन्न नवीन मॉड्यूलों के माध्यम से खेतों में नई तकनीकों के विस्तार के लिए शोधकर्ताओं को किसानों के साथ अंतिम मील की कनेक्टिविटी प्रदान करती हैं।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से कई केंद्र प्रायोजित योजनाएं संचालित करता है। दोहराव से बचने, अभिसरण सुनिश्चित करने और राज्यों को लचीलापन प्रदान करने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऐसी सभी योजनाओं को दो व्यापक योजनाओं में युक्ति संगतिकरण करने की मंजूरी दी है, अर्थात, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) और कृषोन्नति योजना (केवाई)। दोनों योजनाओं के कई और विविध उद्देश्य हैं, लेकिन मोटे तौर पर, पीएम-आरकेवीवाई टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देगी, जबकि केवाई खाद्य सुरक्षा और कृषि आत्मनिर्भरता का समाधान करेगी। 1,01,321.61 करोड़ रुपये के कुल प्रस्तावित व्यय के साथ स्वीकृत, दोनों योजनाएं कृषि, पोषण सुरक्षा, स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, मूल्य शृंखला विकास और निजी क्षेत्र की भागीदारी की उभरती चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करेंगी। सभी घटकों के कुशल और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जाएगा। अम्ब्रेला योजनाओं ने राज्य सरकारों को उनकी राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर एक घटक से दूसरे घटक में धनराशि के पुन: आवंटन के लिए लचीलापन प्रदान किया है। अब, राज्य प्रत्येक योजना के लिए योजनाओं को मंजूरी देने के बजाय केंद्रीय मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के लिए एक व्यापक वार्षिक कार्य योजना तैयार कर सकते हैं। मृदा देखभाल प्रबंधन, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण, कुशल जल प्रबंधन, कृषि-स्टार्टअप आदि से संबंधित व्यक्तिगत योजनाओं को पीएम-आरकेवीवाई के तहत शामिल किया गया है।

कार्यनीति और कदम

सरकार ने छह सूत्री कार्यनीति अपनाकर कृषि के समग्र विकास और किसानों के सामाजिक कल्याण पर अपना जोर फिर से बढ़ाया है। उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन लागत में कमी, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य, प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई, कृषि का विविधीकरण और मूल्य संवर्धन तथा प्राकृतिक खेती कार्यनीति के प्रमुख क्षेत्र हैं। डिजिटल पहल के तहत, देश भर में कृषि कीट निगरानी और कीट प्रबंधन को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली (एनपीएसएस) शुरू की गई है। मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से संचालित इस प्रणाली में 61 फसलों के लिए कीट पहचान मॉड्यूल और समय पर सलाह जारी करने के लिए 15 फसलों के लिए निगरानी मॉड्यूल शामिल है। दिनांक 15 अगस्त, 2024 को इसके लॉन्च होने के बाद से, एक महीने के भीतर, 16,000 से अधिक किसानों ने एनपीएसएस ऐप डाउनलोड किया और 61 से अधिक फसलों के लिए कीटों की

पहचान की। एनपीएसएस ऐप पर 22,300 से अधिक सर्वेक्षण भी किए गए हैं।

खेतों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक विशेष कदम के रूप में, प्रधानमंत्री ने 61 फसलों की 109 किस्में जारी कीं, जिनमें 34 खेत की फसलें और 27 बागवानी फसलें शामिल हैं। नई किस्मों में अनाज, बाजरा, दालें, तिलहन, सब्जियां, फल, मसाले, औषधीय पौधे आदि सहित कई तरह की फसलें शामिल हैं। इन किस्मों को आईसीएआर (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) द्वारा जलवायु परिवर्तन, प्रकृति की अनिश्चितता, कीटों के हमले, पोषण संबंधी कमियों आदि जैसी नई चुनौतियों से निपटने के लिए विकसित किया गया है। आईसीएआर, कृषि विश्वविद्यालयों और राज्यों ने मिलकर इन किस्मों के बीजों को जल्द से जल्द किसानों तक पहुंचाने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है। इसके अलावा, कृषि मंत्रालय ने किसानों को किफायती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण बीज प्राप्त करने में मदद करने के लिए एसएटीएचआई (बीज प्रमाणीकरण, पता लगाने की क्षमता और समग्र सूची) पोर्टल पर 266 प्रजनक बीज-उत्पादन केंद्रों को शामिल किया है।

सरकार ने किसानों के साथ संचार और संपर्क को मजबूत करने के लिए एक नया टीवी और रेडियो कार्यक्रम 'कृषि चौपाल' शुरू करने का फैसला किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि-इनपुट के कुशल उपयोग सहित सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों और कार्य नीतियों को बढ़ावा देकर उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए किसानों को सशक्त बनाना है। एक प्रमुख विशेषता के रूप में, 'कृषि चौपाल' किसानों को अपनी भाषा में इंटरैक्टिव सत्रों के माध्यम से कृषि विशेषज्ञों से सीधे जुड़ने की अनुमति देगा। किसानों को सब्सिडी, इनपुट आपूर्ति, सेवाओं, कार्यक्रमों, योजनाओं आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर अपने प्रश्नों या शिकायतों को दर्ज करने में सहायता के लिए एक बहु-चैनल सहायता के रूप में जल्द ही एक अनूठी किसान शिकायत निवारण प्रणाली (एफजीआरएस) की शीघ्र ही शुरुआत होगी। इससे शिकायत की स्थिति की वास्तविक समय ट्रैकिंग और कार्यक्रम पर स्वचालित अपडेट के साथ बहुभाषी सहायता मिलेगी।

इस वर्ष, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के कवरेज को और बढ़ाने के लिए, संबंधित बैंक शाखाओं के माध्यम से केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) खाताधारक किसानों को संतृप्त करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। एक और राज्य, झारखंड को भी इस योजना में शामिल किया गया। इन पहलों के परिणामस्वरूप, खरीफ 2024 के लिए बीमित किसानों की कुल संख्या 293 लाख के सर्वकालिक उच्च स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है और कुल बीमित क्षेत्र 365 लाख हेक्टेयर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 12 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज करता है। कृषि अवसंरचना कोष की जारी योजना के तहत, कृषि मंत्रालय ने अपनी 100-दिवसीय कार्य योजना के तहत 7,000 से अधिक बुनियादी ढांचा इकाइयां बनाने, 5,500 करोड़ रुपये की कुल ऋण राशि और विभिन्न परियोजनाओं और परिसंपत्तियों के लिए 7,500 करोड़ रुपये का निवेश जुटाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। 10,000 से अधिक इकाइयों, 6,500 करोड़ रुपये से अधिक के स्वीकृत किए गए ऋण और 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के परियोजना निवेश को आकर्षित करके लक्ष्य को पार कर लिया गया। सरकार ने 25 लाख से अधिक नए किसानों को जोड़ने के लिए पीएम-किसान योजना के तहत संतृप्ति अभियान शुरू किया। इस प्रकार, लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर 9.51 करोड़ किसानों के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है।

टिकाऊ कृषि के एक प्रमुख घटक के रूप में, सरकार ने अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए एक विशेष अभियान का प्रस्ताव दिया है। इस पहल का समर्थन करने के लिए, किसानों को सीधे विशिष्ट इनपुट की आपूर्ति की सुविधा के लिए देश भर में 10,000 आवश्यकता-आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2023-24 से एक अलग और स्वतंत्र योजना के रूप में 'प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन' पहले से ही चल रहा है। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, मूल्य संवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए किसान उत्पादक संगठनों, कृषि-सहकारी समितियों और स्टार्ट-अप को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कुल मिलाकर, वर्ष 2024 में एक कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्गठन और निर्माण हुआ, जो सभी वर्गों और श्रेणियों के किसानों की भलाई सुनिश्चित करते हुए भारतीय कृषि को भविष्य के लिए तैयार करने का प्रयास करता है। ❑